Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 6, October-2021, ISSN 2230-7540

अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता और भारत चीन संबंध

Kuldeep Singh Gavadiya[1]* Dr. Manoj Kumar Baharwal[2]

[1] Research Scholar, Department of Political Science, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan

[2] Research Director, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan

सार – *अफगान युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों ने मुख्यतः तीन पक्षों-अफगान सरकार, तालिबान और संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों पर ध्यान केंद्रित किया है। तीनों सीधे संघर्ष में शामिल हैं और इसके अभियोजन और अंतिम समाधान में तत्काल हिस्सेदारी है। 31 अगस्त, 2021 से पहले, अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की वापसी, अनिश्चितता ने अफगानिस्तान की भविष्य की स्थिरता और रुकी हुई शांति प्रक्रिया की संभावनाओं के सवाल को घेर लिया है। अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता का अत्यधिक विरोध किया जाता है। यदि कुछ भी हो, तो अफगान तालिबान के साथ ईरान और रूस के जुड़ाव से पता चलता है कि कैसे ये देश प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और पाकिस्तान से परे आंदोलन के विकल्पों के विविधीकरण में योगदान दे रहे हैं। इस संबंध में, सेशेल्स में हिंद महासागर में अपना पहला सैन्य अड्डा खोलने की चीन की हालिया घोषणा को भारत द्वारा चीन की श्रृणनीतिक घेराबंदी' की नीति के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, भारत चीन-पाकिस्तान-अमेरिका गठजोड़ इस बात की ओर इशारा करता है कि सभी चार राज्य कैसे हैं एक जटिल सुरक्षा संरचना में एक साथ बंधा हुआ है जिसमें बैंडविगनिंग और संतुलन, या दूसरे शब्दों में, जुड़ाव और नियंत्रण दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान-चीन संबंधों से खफा भारत; भारत-अमेरिका संबंधों ने चीन को परेशान किया। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिकार के रूप में देखता है जबकि चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है, खासकर अगर बाद वाला अमेरिका के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करता रहे। अंत में, भारत और चीन दोनों राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियों के रूप में एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के उद्भव में योगदान दे सकते हैं और अमेरिका के विरोध में खड़े हो सकते हैं।*

कुंजीशब्द – *अफगानिस्तान, तालिबानी, सत्ता, भारत चीन संबंध*

----------X----------

प्रस्तावना

अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता

29 फरवरी, 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त करने के लिए दोहा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो 2018 में एक पाकिस्तानी जेल से रिहा हुआ था और तालिबान नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा के डिप्टी हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहुत अंत तक समझौते के संदेह में, बरादर ने ज़ाल्मय खलीलज़ाद के बाद ही हस्ताक्षर किए, यू.एस. जिस दूत ने इस सौदे को देखने के लिए कई साल समर्पित किए हैं, उसने दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर किए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ दर्शकों में पहली पंक्ति में बैठे। तालिबान का एक बड़ा समूह प्रतिनिधि पीछे बैठे, बरादर-खलीलज़ाद समझौते की जय-जयकार कर रहे थे।[1]

हजारों मील दूर, काबुल में, अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर एक समाचार सम्मेलन में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के बगल में खड़े थे और एक संयुक्त घोषणा जारी की। इसने एक व्यापक और स्थायी शांति समझौते के लिए चार चरणों की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की, जिसकी परिणति एक स्थायी और व्यापक युद्धविराम में हुई। कुछ दिन पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने गठबंधन सहयोगियों, साथ ही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और रूस के साथ शांति समझौते के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया था।

www.ignited.in

पिछले चार दशकों में अफगानिस्तान की प्रमुख चुनौती क्षेत्रीय सत्ता प्रतिद्वंद्विता के संयोजन में इसका खंडित घरेलू राजनीतिक परिदृश्य रहा है जिसने इन संघर्षों को और तेज कर दिया है। इस प्रकार एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान चीन सहित अधिकांश पड़ोसी देशों के लिए स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करेगा। इस क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में, चीन को अफगान संकट से निपटने में कुछ फायदे हैं। अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता में गैर-हस्तक्षेप की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति के कारण इसे एक तटस्थ पड़ोसी होने की प्रतिष्ठा मिली है। यहां तक कि जब बीजिंग ने लगभग एक दशक पहले अपनी ऐतिहासिक स्थिति में वृद्धिशील बदलाव का संकेत दिया था, तब भी वह एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए सावधान था, तालिबान सहित सभी प्रमुख अफगान हितधारकों के साथ संबंध स्थापित करना। चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत ने काबुल के लिए बीजिंग के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना अनिवार्य बना दिया है। अमेरिकी वापसी के संदर्भ में, अफगान सरकार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना जारी रखेगी। हालांकि सहायता की प्रकृति निश्चित रूप से बदल जाएगी, 28 चीन एक संभावित स्रोत हो सकता है। हालांकि, पाकिस्तान के साथ चीन का मजबूत विश्वास बीजिंग की मुख्य ताकत है। चूंकि अफगानिस्तान एक भूमि से घिरा देश है जो अपने व्यापार के लिए ज्यादातर पाकिस्तान पर निर्भर है, इसलिए सीपीईसी में इसकी भागीदारी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए फायदेमंद होगी।[2]

हालांकि यह पत्र कार्रवाई के लिए विशिष्ट नुस्खे प्रदान करता है, इसका उद्देश्य अंततः बहस को प्रोत्साहित करना है। इसे लिखने में, हम किसिंजर के दो और सिद्धांतों की तुलना में अधिक प्रशंसनीय हैं राजनेता को केवल एक अनुमान की अनुमति है, और राजनेता को उन आकलनों पर कार्य करना चाहिए जिन्हें उस समय साबित नहीं किया जा सकता है कि वह उन्हें बना रहा है। संक्षेप में, इस पत्र का उद्देश्य अतीत में किए गए नीतिगत निर्णयों का दूसरा अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए रणनीतिक कार्रवाइयों का एक सेट पेश करना है। पिछले एक दशक में इस संघर्ष पर नज़र रखने वाले एक करीबी अफगान चौकीदार के रूप में कहते हैं, अमेरिका छोड़ने का संयोजन, काबुल में एक विभाजित सरकार, और अब कोरोनावायरस, संकट नई और तेजी से बदलती वास्तविकताओं को प्रस्तुत करता है।[3]

चीन को पाकिस्तान की जरूरत

पाकिस्तान के साथ अपनी अफगान नीतियों का समन्वय करना चीन के लिए फायदेमंद होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध है। चूंकि पाकिस्तान के पास अफगान मामलों से निपटने का बहुमूल्य अनुभव है, इसलिए चीन इसे एक बड़े लाभ के रूप में देखता है। एक बार जब चीन ने अफगानिस्तान पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, तो पाकिस्तान अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आगे आया, जिससे दोनों के बीच विश्वास पैदा हुआ। यह अफगानिस्तान के संबंध में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के ठीक विपरीत है। यद्यपि इस्लामाबाद ने वाशिंगटन के साथ अपनी साझेदारी से समृद्ध सैन्य और आर्थिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग एक-दूसरे की विश्वसनीयता और उद्देश्यों के अविश्वास और संदेह से प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत, चीन और पाकिस्तान के बीच अधिक सामरिक अनुरूपता ने अफगानिस्तान में उनके सहयोग को सुगम बनाया है।

पाकिस्तानी प्रभाव

दूसरे संबंधित जोखिम का संबंध अफगानिस्तान में आईएसआई के बढ़ते प्रभाव से है। तालिबान (विशेषकर हक्कानी समूह) और आईएसआई के बीच गठजोड़ देश के भीतर पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। तालिबान नेतृत्व हमेशा पाकिस्तानी राज्य और आईएसआई के साथ नजर नहीं मिलाता है, लेकिन तालिबान पर आईएसआई का प्रभाव निर्विवाद है। वे हमारे शक्तिशाली पहरेदार हैं कि कैसे तालिबान के एक पूर्व संस्थापक सदस्य ने आईएसआई के साथ अपने संबंधों को संक्षेप में बताया। निकट भविष्य में काबुल में तालिबान के प्रतिनिधित्व की संभावना को देखते हुए, यह स्थिति स्वाभाविक रूप से भारत के लिए सहज नहीं है।[4]

भारत के साथ आपसी प्रतिद्वंद्विता

जबकि चीन और रूस कई मुद्दों पर रणनीतिक सहयोग में नए सिरे से रुचि दिखा रहे हैं, जिनमें से अफगानिस्तान एक है, चीन अभी भी पड़ोसी भारत के साथ आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण पाकिस्तान को अधिक विश्वसनीय सहयोगी मानता है। बीजिंग के लिए, कोई भी देश इस क्षेत्र में पाकिस्तान के समान प्रासंगिक और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक नहीं है। यह भारत-पाकिस्तान संबंधों का एक सतत आयाम है और भारत में जम्मू और कश्मीर के समावेश को 'पूर्ववत' करने की पाकिस्तान की चिरस्थायी इच्छा से जुड़ा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 1971 की हार और बांग्लादेश के बाद के जन्म तक, पाकिस्तान के सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के पास भारत से निपटने के तरीके के बारे में काफी सीमित विचार थे। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान की 1971 की हार पर प्रतिक्रिया परमाणु रास्ते पर चलने और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की थी। तब से, पाकिस्तानी सेना के

www.ignited.in

नेतृत्व के भीतर प्रभावशाली समूहों का मानना है कि भारत के खिलाफ बल का गुप्त उपयोग भारत को घुटनों पर लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। और चीन भारत के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक दृष्टिकोण का शुद्ध लाभार्थी रहा है।[5]

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत के साथ आपसी प्रतिद्वंद्विता का अध्ययन

2. अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का अध्ययन

शमन रणनीतियाँ: दूसरों के साथ और उनके माध्यम से कार्य करना

जुलाई 2019 में, बीजिंग में विश्व शांति मंच को संबोधित करते हुए, पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने राजनयिकों और पत्रकारों से भरे एक कमरे में कहा कि अफगानिस्तान के भविष्य में चीन और रूस द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण महत्व की है। करज़ई, जिन पर वार्ताकार 2012 में शांति वार्ता की संभावनाओं को धूमिल करने का आरोप लगाते हैं, फिर एक कदम और आगे बढ़ गए। चीन, करजई ने स्पष्ट किया, अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद शांति प्रक्रिया के गारंटर की भूमिका निभा सकता है। रूस, उन्होंने जारी रखा, चीन के साथ साझेदारी कर सकता है। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि भारत, पाकिस्तान, ईरान और अन्य शामिल हो सकते हैं। करजई ने स्पष्ट किया कि वह जमीन पर चीनी जूतों की वकालत नहीं कर रहे थे। वह अधिक राजनीतिक और कूटनीतिक शब्दों में अधिक चीनी भागीदारी का सुझाव दे रहे थे। उसका वास्तव में क्या मतलब था यह स्पष्ट नहीं है। बयान चौंकाने वाला था, कम से कम कहने के लिए, विशेष रूप से दर्शकों में अमेरिकियों और भारतीयों के लिए। अधिकांश पर्यवेक्षकों के लिए, करज़ई ने व्यापक रूप से, चीन और रूस द्वारा अफगानिस्तान में वास्तव में निभाई जा सकने वाली संभावित भूमिका की अधिक बिक्री की।[6]

आतंक

जोखिमों का पहला सेट अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय आतंकवाद की संभावना से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अफगान सरकार के बीच संयुक्त घोषणा में उल्लिखित चार मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों या व्यक्तियों द्वारा अफगान धरती के उपयोग को रोकने की गारंटी शामिल है। ये शब्द भले ही सुविचारित हों, लेकिन इन गारंटियों को कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर बहुत कम स्पष्टता है। आखिरकार, जिन गुटों में सुलह होनी है, उनमें वे तत्व भी शामिल होंगे जिन्होंने अफगानिस्तान के भीतर से भारत के खिलाफ आईएसआई के युद्ध का सामना किया है। इस दावे का समर्थन करने वाले सबूत भारी हैं।[7]

व्यापार और कनेक्टिविटी

व्यापार, निवेश और सीमा पार से जुड़ाव के अवसर - अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में अंतिम आवर्ती विषय - मध्य एशिया, अरब सागर और भारत के साथ-साथ व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के माध्यम से दोनों पक्षों को अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकता है। आज तक, खतरे की धारणा ने आर्थिक जुड़ाव की संभावनाओं को सीमित कर दिया है, और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रियायतों को सुरक्षित करने के लिए व्यापार पहुंच का लाभ उठाया है। अधिक विनियमित व्यापार के अभाव में, सीमावर्ती समुदाय माल और नशीले पदार्थों के अवैध आदान-प्रदान से समृद्ध हुए हैं, जिसके बिना कई लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।[8]

भारत चीन संबंध

भारत और चीन को शिक्षाविद, रणनीतिक विशेषज्ञ, आर्थिक भविष्यवक्ता, राजनेता और पत्रकार 21वीं सदी की दो उभरती हुई शक्तियों के रूप में देखते रहे हैं। रॉबिन मेरेडिथ के अनुसार, चीन और भारत का उदय शीत युद्ध के बाद की भू-राजनीति में एक बड़े बदलाव के बारे में है, तेल की बढ़ती प्यास को बुझाने के बारे में और बड़े पैमाने पर पर्यावरण परिवर्तन के बारे में है। यह है विवर्तनिक अर्थशास्त्र: भारत और चीन के उदय ने पूरी पृथ्वी के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को हमारी आंखों के सामने बदल दिया है।" राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, जैसा कि हंस मोर्गेंथौ द्वारा उल्लिखित है, दोनों राष्ट्र-राज्यों में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, जिसमें सामरिक गहराई के साथ एक बड़े क्षेत्र के साथ-साथ एक बड़ी आबादी भी शामिल है जो सैन्य गतिविधियों और देश की रक्षा में लगी हो सकती है।

पिछले तीन दशकों में दोनों देशों की बढ़ती आर्थिक क्षमता के साथ राष्ट्रीय शक्ति के शास्त्रीय तत्वों की पुष्टि हुई, जब उन्होंने विकास के अपने-अपने समाजवादी मॉडल को अधिक बाजार-उन्मुख, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में समाप्त कर दिया। इसके अलावा, भारत और चीन दोनों ही हजारों वर्षों से फैली ऐतिहासिक और पुरानी सभ्यतागत पहचान का दावा करते हैं। 20वीं शताब्दी में, भारत और चीन के बीच संबंध

अनुकूल से संघर्षपूर्ण हो गए हैं, मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों पर सामरिक संघर्षों और क्षेत्रीय वर्चस्व पर प्रतिद्वंद्विता के कारण। यह कारक दोनों राज्यों के बीच सहयोग की संभावना को समाप्त नहीं करता है और न ही समाप्त करता है और यह भारत और चीन के बीच 21 वीं सदी में सहयोग और संघर्ष की प्रवृत्तियों का विश्लेषण है कि वर्तमान पेपर का संबंध है।[9]

भारत-चीन संबंध और दक्षिण एशिया पाकिस्तान को समीकरण में शामिल करना

ऐतिहासिक रूप से, उत्तर-औपनिवेशिक युग के तत्काल बाद में, यह भारत और चीन थे जिन्होंने पाकिस्तान के विरोध में दोस्ती के रिश्ते को मान लिया था, जो कि कम्युनिस्ट विरोधी गुट के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध था। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को महत्व दिया और 1950 के दशक के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO) और केंद्रीय संधि संगठन (CENTO) जैसे अमेरिकी-प्रभुत्व वाले गठबंधनों में शामिल हो गए। 1962 के भारत-चीन सीमा युद्ध ने पाकिस्तान के भारत-चीन गठजोड़ में प्रवेश की शुरुआत की और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में नई कूटनीति को बढ़ावा दिया। उस वैचारिक पहलू को नज़रअंदाज़ करते हुए जिसमें इस्लाम और नास्तिक कम्युनिस्ट-विरोधी प्रवचन हावी थे, पाकिस्तान ने अब चीन के साथ गठबंधन करके अपनी विदेश नीति को और अधिक यथार्थवादी-व्यावहारिक अभिविन्यास की ओर फिर से कल्पना की। भारत और चीन के बीच पाकिस्तान के प्रवेश का दोनों देशों के बीच संबंधित संबंधों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और यह भारत चीन संबंधों में पाकिस्तानी कारक के विश्लेषण की दिशा में है।[10]

तालिबान को चीन से राजनयिक और आर्थिक समर्थन की संभावना

अफगानिस्तान को लेकर लग रहे आरोपों से चीन इंकार करता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में स्ट्रेटजिक स्टडी के प्रोफेसर ब्रह्म चेलानी ने इस मामले में चीन को लेकर अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन के लिए जरूरी दो चीजें (राजनयिक मान्यता और आर्थिक सहायता) मुहैया कराने की संभावना ने चिंता बढ़ा दी है।

अफगानिस्तान में अब तक चीन की बड़ी भूमिका नहीं रही

अफगानिस्तान में अब तक चीन की कोई बड़ी भागीदारी नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका संबंध मजबूत रहा है। अफगानिस्तान खनिज संपदा से सम्पन्न देश है। इसमें लिथियम के बड़े भंडार शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी कंपोनेंट है।

जैसे-जैसे आंतरिक वैचारिक संघर्ष तेज हुआ है, स्व-घोषित इस्लामिक स्टेट के खुरासान प्रांत (ISK) को प्रमुखता मिली है। अफगानिस्तान के विशेषज्ञ एंटोनियो गिउस्टोज़ी ने किंग्स कॉलेज लंदन में हाल ही में एक वार्ता में उल्लेख किया कि आईएसके का उद्देश्य अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का ष्सबब्रांडष् बनाना है। ISK खुद को तालिबान के भागीदार के रूप में पेश नहीं कर रहा है, बल्कि एक बेहतर, अधिक शुद्धतावादी और अधिक हिंसक विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। समूह सशस्त्र युवाओं को वित्तीय और वैचारिक दोनों रूप से बेहतर संभावनाएं प्रदान करता है, जिन्होंने 2016 में लगभग 271 मिलियन डॉलर जुटाए थे। तब यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आईएसके ने चीन-केंद्रित समूहों के साथ-साथ अफगान और पाकिस्तानी तालिबान से अलग-अलग गुटों को आकर्षित किया है। 2017 तक, ISK सेनानियों की कुल संख्या का अनुमान कथित 6,000-8,000 से घटकर लगभग 1,000-1,500 हो गया है।[11]

उपसंहार

कूटनीतिक दृष्टिकोण के लिए भारत को अफगान तालिबान से आधिकारिक तौर पर बात करने के लिए अपनी पारंपरिक अनिच्छा को त्यागने की आवश्यकता होगी। इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि सभी अफगान तालिबान गुट पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं, सभी तालिबान भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और उनमें से कई सक्रिय रूप से कश्मीर-केंद्रित आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ भी हो, 1990 के दशक में ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की कीमत चुकाने के बाद, अफगान तालिबान आज वैश्विक जिहादियों की मेजबानी करने से बहुत सावधान है। निकट भविष्य में नई दिल्ली के लिए सबसे आकर्षक नीति विकल्प अफगानिस्तान को निरंतर विकासात्मक समर्थन के साथ अपने राजनयिक दृष्टिकोण को जोड़ना है। गंभीर रूप से, यह भारत को पिछले पंद्रह वर्षों के लाभ को कम किए बिना अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने की अनुमति देगा, भले ही कोई भी शक्ति सुलह प्रक्रिया का नेतृत्व करे। भारतीय अधिकारी आमतौर पर पूछते हैं कि उन्हें तालिबान से किस बारे में बात करनी चाहिए, यह तर्क देते हुए कि आंदोलन सिर्फ अपने लिए सत्ता को मजबूत करना चाहता है। यह सच है। लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता का अत्यधिक विरोध किया जाता है। यदि कुछ भी हो, तो अफगान तालिबान के साथ ईरान और रूस के जुड़ाव से पता चलता है कि कैसे ये देश प्रभाव के लिए

www.ignited.in

प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और पाकिस्तान से परे आंदोलन के विकल्पों के विविधीकरण में योगदान दे रहे हैं। इस संबंध में, सेशेल्स में हिंद महासागर में अपना पहला सैन्य अड्डा खोलने की चीन की हालिया घोषणा को भारत द्वारा चीन की श्रणनीतिक घेराबंदी' की नीति के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, भारत चीन-पाकिस्तान-अमेरिका गठजोड़ इस बात की ओर इशारा करता है कि सभी चार राज्य कैसे हैं एक जटिल सुरक्षा संरचना में एक साथ बंधा हुआ है जिसमें बैंडविगनिंग और संतुलन, या दूसरे शब्दों में, जुड़ाव और नियंत्रण दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान-चीन संबंधों से खफा भारत; भारत-अमेरिका संबंधों ने चीन को परेशान किया। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिकार के रूप में देखता है जबकि चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है, खासकर अगर बाद वाला अमेरिका के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करता रहे। अंत में, भारत और चीन दोनों राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियों के रूप में एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के उद्भव में योगदान दे सकते हैं और अमेरिका के विरोध में खड़े हो सकते हैं। हालांकि, वास्तविकता (अभी के लिए) यह है कि दोनों राज्यों को अमेरिका की जरूरत है और उस समय तक, राजनीतिक शक्ति के वैश्विक पुनर्गठन की संभावना धूमिल बनी हुई है।[12]

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. ललित मानसिंह के साथ लेखक का साक्षात्कार (पूर्व.) भारत के विदेश सचिव) 2013।

2. 'भारत ईरान में अफगानिस्तान पर बैठक में भाग लेगा,' टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 अक्टूबर 1996।

3. हनीफ उर रहमान, 'पाकिस्तान-अफगान संबंधों के दौरार्न भुट्टो एरा: द डायनेमिक्स ऑफ कोल्ड वॉर,' पाकिस्तान जर्नल ऑफ हिस्ट्री और संस्कृति 33, नहीं। 2 (2012): 28.

4. नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग, मंत्रालय विदेश मामलों की वार्षिक रिपोर्ट (नई दिल्ली: मंत्रालय विदेश मामलों के, 1996)।

5. बार्नेट आर रुबिन और अबूबकर सिद्दीकी, 'पाकिस्तान-अफगानिस्तान गतिरोध का समाधान,' विशेष रिपोर्ट संख्या। 176, संयुक्त राज्य अमेरिका शांति संस्थान, अक्टूबर 2006, 7, www-usip-org/publications/2006/10/resolving-pakistan-Afghanistan-stalemate

6. शुजा नवाज, क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स: पाकिस्तान, इट्स आर्मी, एंड द वार्स विदिन (कराची: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008), 439

7. हनीफ उर रहमान, 'पाकिस्तान-अफगान संबंधों के दौरार्न भुट्टो एरा: द डायनेमिक्स ऑफ कोल्ड वॉर,' पाकिस्तान जर्नल ऑफ हिस्ट्री और संस्कृति 33, नहीं। 2 (2012): 28.

8. वी. सुदर्शन, 'हाउ इंडिया सीक्रेटली आर्म्ड अफगानिस्तान्स नॉर्दर्न एलायंस,' द हिंदू, 1 सितंबर 2019 www-thehindu-com समाचार

9. पीटर ब्यूमोंट और सईद कमाली देहगान, 'डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया' 'आतंकवादियों और मिलिशिया' के लिए,' अभिभावक, 22 मई, 2017, https://www-theguardian-com/us-news/2017/मई/22/ईरान-डोनाल्ड-ट्रम्प-हसन-रूहानी-इज़राइल।

10. सलमान मसूद, मुजीब मशाल, और हरि कुमार, 'पाकिस्तान और भारत ने ट्रबल बॉर्डर पर संघर्ष विराम पर फिर से शपथ ली,' न्यूयॉर्क टाइम्स, 25 फरवरी, 2021, nytimes-com/2021/02/25/world@asia/Pakistan-indi/ceasefire-html.

11. सुशांत सिंह, 'अफगानिस्तान भारत की शक्ति की सीमाएं दिखाता है,' विदेश नीति, 22 अप्रैल, 2012, www-foreignpolicy-com/2021/04/22/अफगानिस्तान-भारत-संयुक्त-राज्य-प्रस्थान।

12. राज्य परिषद, 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव,' चीन जनवादी गणराज्य, जून 15, 2017 को अभिगमित http://english-gov-cn/beltAndRoad/A

Corresponding Author

Kuldeep Singh Gavadiya*

Research Scholar, Department of Political Science, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan